

बिज़नेस स्टैंडर्ड

वर्ष 12 अंक 92

नई ऊंचाई

समाहांत पर आई बुरी खबरों के बाद सोमवार को शेयर बाजारों के पास तेजी की वजह थी और वह देखने को मिली भी। सेसेक्स पहली बार 40,000 अंक के ऊपर चंगे हुआ और निपटी ने पहली बार 12,000 का आकड़ा पार किया। मार्च तिमाही का जीडीपी अंकड़ा कमज़ोर है और मंदी का संकेत देता है। मई में वाहानों की बिक्री में मंदी रही और वर्ष 2018-

19 की चौथी तिमाही में कारोबारी आय को निराशजनक रही। कारोबारी जगत के दिग्गज इस बात को लेकर एकमत है कि अब तक अश्वेष्यवर्थ को गति देती आई खपत भी कमज़ोर पड़ रही है। इसके बावजूद चूंकि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भारतीय बाजार कमज़ोर है और मंदी का संकेत देता है। मई में रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है। वर्ष

2018 में 34,000 करोड़ रुपये की विशुद्ध बिकवाली के बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 2019 में अब तक 78,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इस निवेश ने बाजार को गति दी है।

रुख में यह बदलाव फरवरी में देखने को मिलने लगा जब विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने डॉलर में निवेश शुरू किया। मार्च 2019 भारतीय बाजारों के इतिहास का दूसरा सबसे अधिक शुद्ध निवेश वाला महीना रहा। उनके रुख में इस बदलाव की वजह थी अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा बढ़ती व्याज दरों के चक्र के अंत की घोषणा। इसके परिणामस्वरूप अमेरिकी बॉर्ड प्रतिफल नवंबर 2018 के 3.24 फीसदी के उच्चतम स्तर से घटकर अब 2.12 फीसदी रह गया है। यह पांच वर्ष के निचले

स्तर के करीब है। बॉर्ड और व्याज दरों में कर्मी के कारण इविवटी में निवेश, तयशुदा आय परिसंपत्तियों को तुलना में कर्हीं अधिक

देश के चाल खाते का घाटा कम हो सकता है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की दृष्टि से भारत का बाजार आकर्षक है और चौथी तिमाही के कमज़ोर जीडीपी अंकड़े के बावजूद इसमें विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भारतीय बाजार को गति दी है।

अमेरिकी बॉर्ड अब उच्च प्रतिफल वाला सुरक्षित निवेश नहीं रह गए और फेडरल रिजर्व की व्याज दरों संबंधी घोषणा के बाद भारत इस धन की आवक को दृष्टि से सबसे बड़ा लाभार्थी बनकर उभरा। अमेरिकी बॉर्ड प्रतिफल में गिरावट के साथ-साथ भारत में 10 वर्ष के मानक प्रतिफल में भी गिरावट आई और यह सितंबर के 8.18 फीसदी से गिरकर सोमवार को 7 फीसदी हो गया। ब्रेंट बॉर्ड ऑयल की कीमत भी मई में मध्य से 14 फीसदी कम है। इससे भारतीय विनियोगियों के काचे माल की लागत आने वाले दिनों में घट सकती है और

रहे हैं। नकदी के कारण अधिमूल्य नकी अवधि भी भारतीय शेयर बाजारों के लिए नई नहीं है। डॉलर की आवक के अलावा हालिया तेजी के लिए कई अन्य कारक उत्तरदायी हैं। ताकालिक बात करें तो बाजार आश कर रहा है कि इस सासाह मौद्रिक नीति समिति की बैठक में 25 अधिकारी अंकों की कटौती देखने को मिल सकती है। बाजार वित्त मंत्री निवेश सीतारमण के 5 जूलाई को आने वाले बजट से भी कुछ प्रोत्साहन और व्यय में इंजाफ़े की अपेक्षा कर रहा है। इससे मांग और बृद्धि को गति मिल सकती है। विदेशी निवेश, कच्चा माल की स्थायित्व की ओर निवारी नीति, किसी आय प्रतिफल से अधिक है। यह भी एक कारण है कि विदेशी निवेशक भारत पर दांव आजमा दिख रहा है।



विनय ठिक्का

देश की नई वित्त मंत्री के लिए 6 सुझाव

प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार और नई वित्त मंत्री को सलाह दे रहे हैं तमाल बंदोपाध्याय

देश में आगामी पांच वर्ष के लिए एक अलंकृत मजबूत सरकार बन चुकी है।

केंद्रीय बैंक में भी एक व्यावहारिक गवर्नर है। यही कारण है कि मैं देश की नई वित्त मंत्री के सम्बन्ध छह अन्याही सलाह प्रस्तुत करने का उत्साह जुटा सका हूं। उनमें से कुछ सलाह कठोर प्रतीत हो सकती हैं लेकिन भाजपा की यह सरकार भी निनाय लेने में सक्षम और मिशन मोड पर काम करने वाली है।

सरकारी बैंकों का निजीकरण: वैंकिंग अधिनियम के अधीन सरकार को ऐसे बैंकों में 51 फीसदी चुकाती पूंजी रखना अनिवार्य है। सरकार के अलावा ऐसे बैंकों तथा अन्य सरकारी उपक्रमों में भारतीय जीवन बीमा निगम भी अच्छी खासी हिस्सेदारी रखता है। यही बैंकों की आपस में क्रॉस होलिंग भी है, यानी सरकार का पूरा नियंत्रण सुनिश्चित है।

इसमें बदलाव करने की आवश्यकता है। बैंकों दो वर्ष में सरकारी बैंकों में अलंकृत होने की व्यावहारिक गवर्नर है। यही कारण है कि मैं देश की नई वित्त मंत्री के सम्बन्ध छह अन्याही सलाह प्रस्तुत करने का उत्साह जुटा सका हूं। उनमें से कुछ सलाह कठोर प्रतीत हो सकती हैं लेकिन भाजपा की यह सरकार भी निनाय लेने में सक्षम और मिशन मोड पर काम करने वाली है।

सरकारी बैंकों का निजीकरण: वैंकिंग अधिनियम के अधीन सरकार को ऐसे बैंकों में 51 फीसदी चुकाती पूंजी रखना अनिवार्य है। सरकार के अलावा ऐसे बैंकों तथा अन्य सरकारी उपक्रमों में भारतीय जीवन बीमा निगम भी अच्छी खासी हिस्सेदारी रखता है। यही बैंकों की आपस में क्रॉस होलिंग भी है, यानी सरकार का पूरा नियंत्रण सुनिश्चित है।

इसमें बदलाव करने की आवश्यकता है। बैंकों दो वर्ष में सरकारी बैंकों में करीब 2 लाख करोड़ रुपये की पूंजी डाली जाए। सरकार 2009 से करीब 3.3 लाख करोड़ रुपये की पूंजी दोनों डाल चुकी है। अगर उसने उन पैसों में निवेश किया होता तो उसकी कापानी आय हुई होती।

एक पैसल ने सभी सरकारी बैंकों के बाद उन्होंने अलंकृत होने की आवश्यकता है।

एक पैसल ने अलंकृत होने की आवश्यक